राज्य-वार कितनी टाडा अदालतें गठित की गईं ;

(ग) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार इन मामलों में राज्य-वार कितने अभियुक्त हैं ;

(घ) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया ;

(ङ) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति नजरबंद है ;

(च) पिछली बार टाडा मामलों की राज्य-वार समीक्षा कब की गई थी ; और

(छ) पिछली बार इन मामलों की केन्द्र सरकार द्वारा कब समीक्षा की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ) यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है, हालांकि अन्य आपराधिक कानूनों की तरह टाडा, 1987 भी केन्द्रीय अधिनियम है लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेवारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की है। टाडा, 1987 के व्यपगत हो जाने के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अभियोजन शाखाओं और पदनामित टाडा न्यायालयों द्वारा लम्बित मुकदमों को तेजी से निपटाया जाना है। एक प्रशासनिक उपाय के रूप में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर बार-बार अनुरोध किया गया है कि लम्बित मामलों की राज्य स्तर पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाए और लम्बित मामलों में विचारण तेज किया जाए, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो और पदनामित न्यायालय सृजित किए जायें। केन्द्रीय स्तर पर टाडा मामलों का नियमित प्रबोधन और पुनरीक्षा की जाती है। इस मामले की पुनरीक्षा करने के लिए अब केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय पैनल गठित किया गया है, जिसकी बैठक जल्दी होगी।

Overstaying of Foreign Nationals

2389. SHRI BHAGABAN MAJHI:

SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of foreign nationals have overstayed in the country;

(b) if so, the approximate number of those nationals;

(c) whether they have gone underground; and

(d) if not, the efforts being made to traceout their whereabouts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (d) As the powers under the Foreigners Act, 1946 to identify, detect and deport foreign nationals residing in the country beyond the validity of visa have been delegated to the State Government UT Administrations, such data is not Centrally maintained. The Government is, however, aware of the problem of foreign nationals residing in the country beyond the validity of their visas. Instructions have been issued to the State Governments/UT Administrations to detect and deport such foreign nationals.

Foodgrains for PDS smuggled to Bangladesh

2390. SHRI AKHILESH DAS:

SHRI SHIV CHARAN SINGH:

SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has since been drawn towards a news-item entitled 'Foodgrains for PDS being

smuggled into Bangladesh' which appeared in the Pioneer (N.D.) dated the 24th July, 1997;

(b) if so, what are the details of the states taken/contemplated by Government to tide over the menace.

(c) what has been the achievement in each case; and

(d) who are the persons suspected to be conniving with smugglers to facilitate such illegal movement of foodgrains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Government are aware that some illegal trade in commodities like salt, sugar, rice and clothes take place in the Indo-Bangladesh border areas.

(b) A number of measures including reduction of gaps between Border Out Posts, intensification and increase in Patrols, erection of Observation Post Towers, use of night vision devices, construction of border roads and fences along sensitive stretches have been taken to check smuggling.

(c) The seizures of essential commodities made by the Border Security Force deployed on Indo-Bangladesh border during the last three years are as follows:

Item	1995	1996	1997 (upto 30 June)
Salt (Kg)	1245838	1699625	1126571
Sugar (Kg)	855447	1567774	867472
Rice (Kg)	2000548	783102	99503
Cloth (worth rupees)	35129536	30524120	18956963

(d) There are reports of alleged involvement of wholesale dealers for Public Distribution System in border districts and owners of sweetmeat shops in the border areas, who are reportedly getting excess allotment of flour and sugar. There have been complaints of general nature against the Border Security Force personnel also. A close watch is kept on the BSF personnel to ensure that they maintain a high standard of rectitude and integrity.

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

2391. **श्री नागमणि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1996 को दिए गए गृह मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ अधिकारियों को अपना दैनिक काम-काज हिन्दी में करना चाहिए और अन्य अधिकारियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए; और

(ख) क्या वे अपने विभाग के वरिष्ठ और अन्य अधिकारियों को इनका अनुपालन करने के निर्देश देंगे और क्या हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में इसकी निगरानी की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) हिन्दी दिवस 1996 के अपने संदेश में गृह मंत्री ने इस आशय का विशेष अनुरोध किया था ।